Poonam Shodh Rachna (ISSN 2456-5563)
(A multidisciplinary, peer reviewed and refereed Research Journal)
Vol.2, Issue.2, February 2023, http://dx.doi.org/10.56642/psr.v02i02.007

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

Author : Mr. Rahees Ahmad, Research Scholar, Economics
H.N.B. Govt. PG College khatima (Kumaun University Nainital)

सार
किसी भी देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो देश की प्रगति में अवरोध का काम करती है किसी भी देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में किसी भी वर्ग शिक्षित या अशिक्षित जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों मे लोगों की आय कृषि पर निर्भर करती है जिस कारण इस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है भारत जैसे देश में संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन इन संसाधनों का उचित विदोहन नहीं हो पा रहा है जिस कारण उनका अनुकूल रूप से उपयोग नहीं हो रहा है इसका एक कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है या उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह उन संसाधनों का उचित विदोहन कर सकें। इसका एक और कारण यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय इतनी नहीं होती है कि वह समर्थ मांग का सृजन कर सकें। इनके पास इतनी पूंजी या वित्त नहीं होता है कि अपना स्वयं रोजगार कर सकें इसका समाज या अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सभी समस्या को दूर करने के लिए नई रणनीतियां तथा नई इकाइयों का उत्पन्न किया जाना आवश्यक है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधी कार्यक्रमों को अपना रही है जिससे कि इन समस्याओं को दूर किया जा सके तथा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को उपलब्ध कराया जा सके। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है अधिकतर जनसंख्या कृषि से रोजगार की प्राप्ति करती है तथा कृषि ही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है लेकिन कृषि में इतनी आय नहीं होती है जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। इस पत्र को लिखने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विश्लेषण इसके विकास एवं महत्व पर प्रकाश डालना है।
मुख्य शब्द : ग्रामीण बेरोजगारी, रोजगार सृजन, रोजगार कार्यक्रम, रोजगार आदि।

प्रस्तावना
भारत की बेरोजगारी के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा आय एवं मजदूरी धन का असमान असंतुलन बेरोजगारी के परिणाम है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है फिर भी वर्तमान में अभी भी बेरोजगारी एक मुख्य समस्या बनी हुई है और समय के साथ यह वर्ष- प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है आज बेरोजगारी की समस्या से कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। यह व्यापक पैमाने पर अपने पैर पसार चुकी है। भारत जैसे देश के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करती है जिससे एक और देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है दूसरी ओर श्रम शक्ति का ह्रास हो रहा है श्रम शक्ति क्षीण होती जा रही है जिससे पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है मानव पूंजी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिकांश लोगों का ध्यान गैर कृषि कार्य की ओर आकर्षित हो रहा है क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं कृषि का आधुनिकरण तथा वाणिज्यीकरण करके कृषि की ओर ध्यान उन्मुक्त किया जाना चाहिए। रोजगार सृजन ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा घटते रोजगार के अवसरों के परिपेक्ष्य में कृषि संबंधित क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान पद्धति
शोधपत्र विशेषण सामग्री तथा रोजगार सृजन एवं बेरोजगारी का अध्ययन करने में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है इन आंकड़ों को पुस्तकों पत्रिकाओं और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर एकत्रित किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य
1- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का विश्लेषण करना
2- ग्रामीण बेरोजगारी का अध्ययन एवं समस्या - समाधान प्रस्तुत करना

बेरोजगारी का तात्पर्य
जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करने में समर्थ है पर उसको प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिल पा रहा है तो इसको बेरोजगार कहा जाएगा। ऐसी ही समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। अन्य शब्दों में जब कोई व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ्य हैं और काम भी करना चाहता है पर उसको प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार कहा जाएगा। मनुष्य केवल उपभोक्ता नहीं होता है बल्कि वह उत्पादक भी होता है और देश निर्माण में भागीदारी भी सुनिश्चित करता है उत्पादक कार्यों में भाग भी लेता है और वह समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी प्रस्तुत करता है। किसी भी व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए रोजगार में होना आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने तथा किसी के अधीन कार्य करने या स्वयं का रोजगार करता है तो वह रोजगार में कार्यरत माना जाता है।

बेरोजगारी के प्रकार
भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को देखा जाए तो इसके कई रूप पाए जाते हैं लेकिन इसके कुछ रूप निम्न है-
1- प्रच्छन्न बेरोजगारी 2- शिक्षित बेरोजगार 3- मौसमी बेरोजगारी 4- खुली बेरोजगारी
5-अल्प बेरोजगारी 6- संरचनात्मक बेरोजगारी

ग्रामीण विकास

अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है ग्रामीण भारतीय क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता बनी हुई है जैसे- कौशल विकास एवं तकनीक, महिला शिक्षा, मानव विकास, स्वच्छता संसाधनों का विकास, भूमि सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, जैसे- पानी, बिजली, सिंचाई, सड़क, सूचना प्रसारण की सुविधा, गरीबी उन्मूलन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

अमर्त्यसेन के अनुसार भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। जहां देश के 91 प्रतिशत लोग गरीबी, 90 प्रतिशत बेरोजगारी और इनसे कहीं अधिक कुपोषण तथा शिक्षा एवं पिछड़ापन के दलदल में फसे हुए हैं। देश की चकाचैंध केवल शहरों में है लेकिन भारत का लोकतंत्र गांवों में बसता है जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सिमट गया है।

''स्माल इज ब्यूटीफुल'' ई एफ सुमाखर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने की बात करते हैं जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी हो। जिनके पास उचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा का अभाव है उन लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ सके।

प्रोफेसर हर्षमैन ग्रामीण अवस्थापना के लिए दो अवस्थापना की बात करते हैं 1. भौतिक 2. समाजिक जिनको हर्षमैन समाजिक उपरिव्यय पूंजी कहते हैं। भौतिक के अंदर यातायात, संवहन, शक्ति को सम्मिलित किया जाता है इसके अतिरिक्त इनमें बैंकिंग बीमा, वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल करते हैं। समाजिक अवस्थापना में जल सफाई सीवेज शिक्षा स्वास्थ्य को सम्मिलित करते हैं।

एम.दंतुलाल, 1979 ग्रामीण रोजगार प्रभाव और उपकरण में बेरोजगारी के कारण क्या है आर्थिक तथा सामाजिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आर. एवं स्टीवर्ट, (1993) : ने अपने अध्ययन में बताया कि रोजगार तथा विविधीकरण विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

जी. के. चड्डा (2002) :में ग्रामीण और गैर कृषि रोजगार की सभी घटना देखी खासकर महिलाओं से संबंधित घटना या ज्यादा थी।

रंजन शरद (2006) : ग्रामीण रोजगार विकसित करने ग्रामीण विकास रोजगार के आधार आय तथा उत्पादकता गरीबी उन्मूलन तथा पलायन हेतु गैर कृषि गतिविधियों को दिखाया है।

भाटिया संदीप कौर 2009 : पंजाब के अध्ययन में यह बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन में विविधीकरण, ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है।

डॉ रवि सिंह (2016) : भारतीय युवाओं के मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है उनमें नौकरी है उद्यम नहीं। आर्थिक विकास उद्यम से ही होकर जाता है।

जगदीश सक्सेना (2017) : हमारे देश में आज भी कृषि, उन्नति और प्रगति का आधार है।

निमिष कपूर (2018) : देश के आर्थिक विकास में वैज्ञानिकों के साथ ही देश के आम नागरिकों की भी भागीदारी निश्चित की जा सकती है।

विनोद कुमार (2018) : ग्रामीण युवाओं में शिक्षा संबंधी स्थिति का अध्ययन तथा शिक्षा कौशल महिलाओं से जुड़े अंतरालों को पाटकर सामाजिक विषमता कम करना है।

ग्रामीण विकास की समस्या

1-गरीबी बेरोजगारी भुखमरी कुपोषण महिला हिंसा की समस्या
2- शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार की समस्या।
3- गांव के पलायन की समस्या।
4- भौतिक सुविधाओं एवं मनोरंजन के अभाव।

भारत में बेरोजगारी के कारण

कृषि- भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करती है जिसका रूप निश्चित नही है यहां कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि का सामना कृषि को करना पड़ता है जिससे की फसलों की बर्बादी या फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है।

कुटीर तथा लघु उद्योग- कुटीर तथा लघु उद्योग इतने विकसित अवस्था में नहीं है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता और इन उद्योगों में लागत भी अधिक होती है जिससे यह अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं और इनके उत्पाद भी इतन सामर्थ्य नहीं होते हैं कि वह फैक्ट्री में बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें जिससे इनको बाजार से बाहर होना पड़ता है। इनकी गुणवत्ता भी इतनी आकर्षक नहीं होती है जो यह फैक्ट्री के उत्पाद के सामने टिक पाए तथा इनकी उत्पाद लागत भी अधिक आती है जिस कारण यह बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर पाते। क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी होती है जो इनके पतन का कारण बनती है क्योंकि इनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह पूर्ण रूप से कार्य कर सकें।

कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था- भारत में कृषि उत्पाद के विपणन की महत्वपूर्ण समस्या है कृषकों के पास अच्छे भंडार ग्रह या गोदाम नहीं है जिससे वह अपनी फसलों को सुरक्षित रख सके इसीलिए वह मध्यस्थों को कम दामों में फसलों को बेच देते हैं। जिससे उनको अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है जिससे उनकी आय में कमी होती हैं और वह निर्धन ही बने रहते हैं जिससे उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल पाती और वह इस समस्या से जूझते रहते हैं।

सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम

देश का आर्थिक विकास करने के लिए सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर विकास किया जाना आवश्यक है। क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है देश में बेरोजगारी का उन्मूलन करने के लिए समय≤ पर विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रमों को अपनाया गया है उन कार्यक्रमों से कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन वह बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पाए हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं जिन्होंने देश में बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम- इस कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 1999 से की गई। इसके साथ ही ग्रामीण महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि करके रोजगार में सतत वृद्धि करना है। और इन कार्यक्रमों को सफल बनाना है

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)- योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से अनंतपुर जिले से हुई 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को विकसित करना है। तथा ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है जिनको वर्ष में कुछ दिनों तक ही रोजगार मिल पाता है यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।

हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना नए भारत का निर्माण तथा सशक्त भारत का निर्माण करना है। किसानों और खेतों से ही होकर भारत निर्माण का सपना पूर्ण हो सकता है। सरकार गांव के विकास की ओर उन्मुख है सामाजिक समानता से सरकार ने 2018 तक सभी के लिए बिजली, 2022 तक सभी के लिए आवास, 2030 तक हर घर जल के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। वित्तीय समावेशन के लिए जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कृषि सिंचाई योजना, हर खेत पानी हर बूंद अधिक फसल का लक्ष्य, मृदा स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सरकार मुख्य रूप से कार्य कर रही है तथा भारत निर्माण में जमीनी स्तर पर विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 3.6 करोड़ महिलाएं मिशन से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1.35 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.60 युवाओं को प्रशिक्षित तथा 79400 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50000 ग्राम पंचायत, 5000 ग्रामीण समूह में सभी परिवारों के लिए स्थाई रोजगार सुनिश्चित करता है। 30 करोड़ खाते जन धन योजना के तहत खोले गए हैं जिनमें 60 प्रतिशत गरीब ग्रामीण खाते हैं।

निष्कर्ष

देश में समावेशी विकास तथा स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक अवसंरचना विकसित की गई है। तथा श्रम सुधार में अनेक उपाय किए जा रहे हैं शिक्षा तथा कौशल विकास का सृजन किया जा रहा है सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करके बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया है। तथा देश में महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित किया है जिससे बेरोजगारी में कमी आई है। और बेरोजगारी पर एक बड़ा प्रहार किया है विभिन्न प्रयासों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार को उपलब्ध कराया है। और बेरोजगारी को कम किया है इन सभी कार्यक्रमों को और भी अधिक सशक्त बनाकर तथा समीक्षात्मक रणनीति को अपनाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- सिंह एस.पी. आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस चंद्र एंड कंपनी रामनगर, नई दिल्ली
2- भगोलीवाल डॉ. टी.एन., श्रम औद्योगिक संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
3- पंत डॉ. जे. सी. मिश्रा एवं डॉ. जे.पी भारतीय आर्थिक समस्या, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
4- चैबे पी.के. भारत का आर्थिक विकास
5- दत्त, रुद्र एवं सुंदरम के.पी.एम. भारतीय, अर्थव्यवस्था चंद कंपनी रामनगर, नई दिल्ली
6,- अग्रवाल, मनोज कुमार एवं निगम सुधीर कुमार, विकास परियोजनाए, नार्दन बुक सेंटर नई दिल्ली
पत्रिका
कुरुक्षेत्र- 2020-21
प्रतियोगिता दर्पण- 2021